B. A- Part-II (Hons)

paper- III A Sub- Geography

TOPIC:- FARMING REGIONS OF INDIA

भारत का कृषि प्रदेश

भारत प्राचीन समय से एक कृषि प्रधान देश रहा है। प्रधान रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत का समाज भी मुख्य रूप से एक कृषिपरक समाज है जिसमें लगभग 70% जनसंख्या अपनी जीविका के लिये कृषि पर निर्भर है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का अंशदान 1951 में 60% से घटकर 2003 में लगभग 25% रह गया तथापि यह अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की जनसंख्या के लिये भोजन की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ कृषि [illegible] उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होते हैं तथा यह [illegible] को रोजगार प्रदान करती है एवं पर्याप्त [illegible] मुद्रा भी अर्जित करती है।

डाबी (Dobby) तथा [illegible] (Whittlesey) सहित अनेक विद्वानों ने भारत में कृषि [illegible] विभिन्न आधारों पर किया है। डाबी ने [illegible] के परिमाण तथा बाजार के आधार पर भारत में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। डाबी के अनुसार [illegible] में चार कृषि प्रदेशों का है-

① पशु पालन कृषि (Pastoral Farming) - यह कृषि पश्चिमी राजस्थान, उत्तर-पश्चिम गुजरात तथा जम्मू एवं काश्मीर में प्रचलित है।

② नम- चावल प्रधान निर्वाहक कृषि (wet rice subsistence farming) - यह कृषि उत्तर-पश्चिम पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल तथा भारत के [illegible] तटीय भागों में प्रचलित है।

③ गेहूं प्रधान मिश्रित निर्वाहक कृषि (Mixed subsistence wheat dominant farming) - यह कृषि [illegible] [illegible] प्रकार की है। [illegible] से सर्वाधिक [illegible]

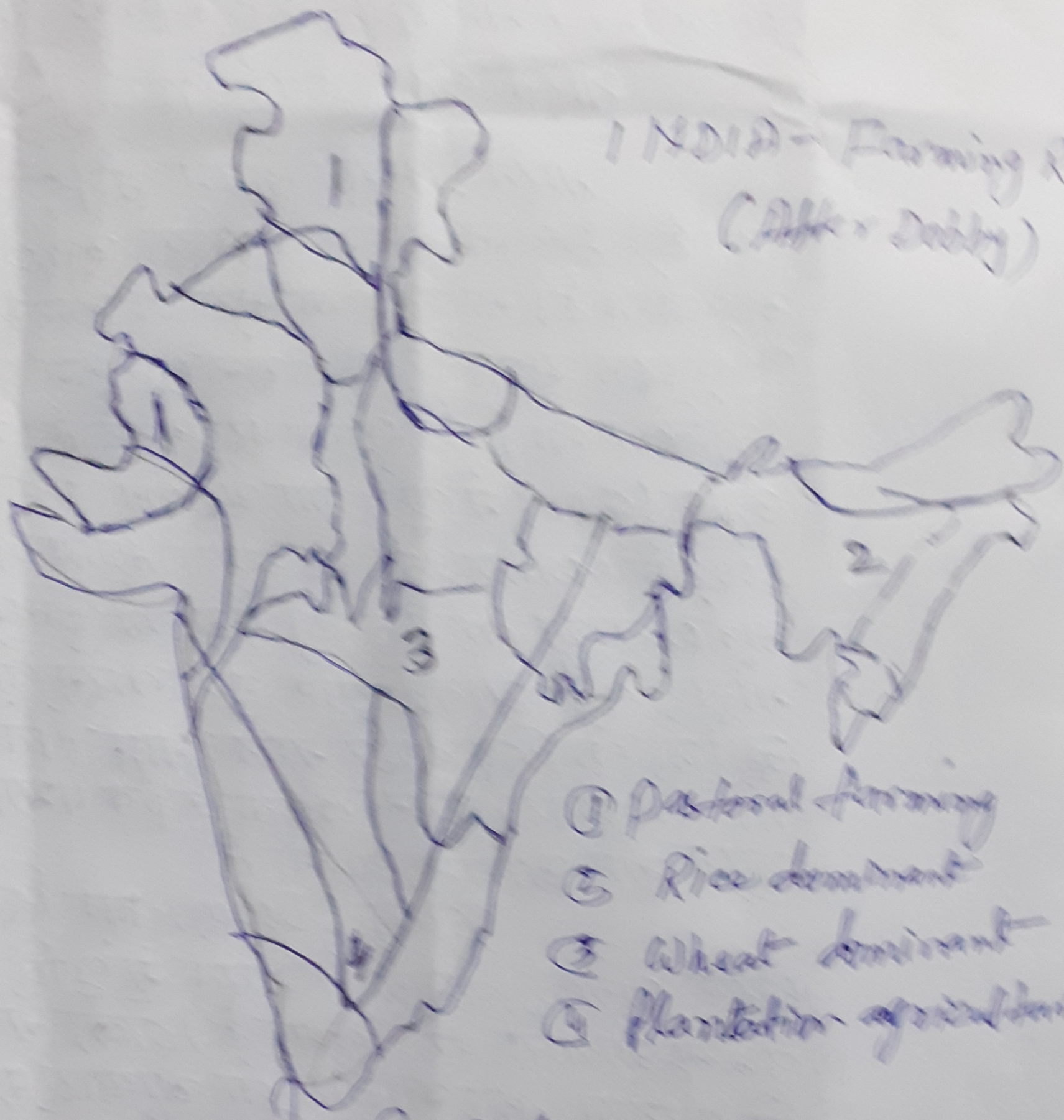

④ बागाती कृषि (Plantation farming) :- यह असम तथा दक्षिणी भारत की पहाड़ी ढालों पर प्रचलित है।

व्हिटलसी (Whittlesey): व्हिटलसी ने भारत को प्रमुख रूप से चार कृषि प्रदेशों में बाँटा है:-

① चलवासी पशुचारण (हिमालय में)

② चावल प्रधान सघन कृषि।

③ चावल विहीन सघन निर्वाहक कृषि।

④ प्राचीन स्थानबद्ध कृषि।

देश के विशाल आकार तथा भौतिक स्वरूप वातावरणीय सामाजिक आर्थिक दशाओं में अन्तर के कारण यहाँ के निवासियों द्वारा विभिन्न कृषि पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं जो निम्न हैं:-

① झूम कृषि या स्थानान्तरी कृषि (Jhuming or shifting cultivation)

यह कृषि 'काटो और जलाओ' (Slash and burn) के रूप में भी जानी जाती है तथा अनेक स्थानीय नामों से ... उत्तरी-पूर्वी राज्यों में इसे 'झूम', आन्ध्र प्रदेश में 'पोडु', केरल में 'पोनम', मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में 'बीवर', 'मशान', 'पेंडा' तथा 'बीरा' तथा दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में 'वालरा' कहा जाता है। यह कृषि विभिन्न राज्यों के विभिन्न आदिवासी वर्गों द्वारा अपनाई जाती है। इस कृषि में वनों को काटकर तथा जलाकर [illegible] भूमि को साफ किया जाता है [illegible] वर्षों तक [illegible] जाती है [illegible] कम हो जाती है, तो इस खेत [illegible] के लिए [illegible] किया जाता है [illegible] खेती के लिए साफ किया जाता है [illegible] पहाड़ [illegible]

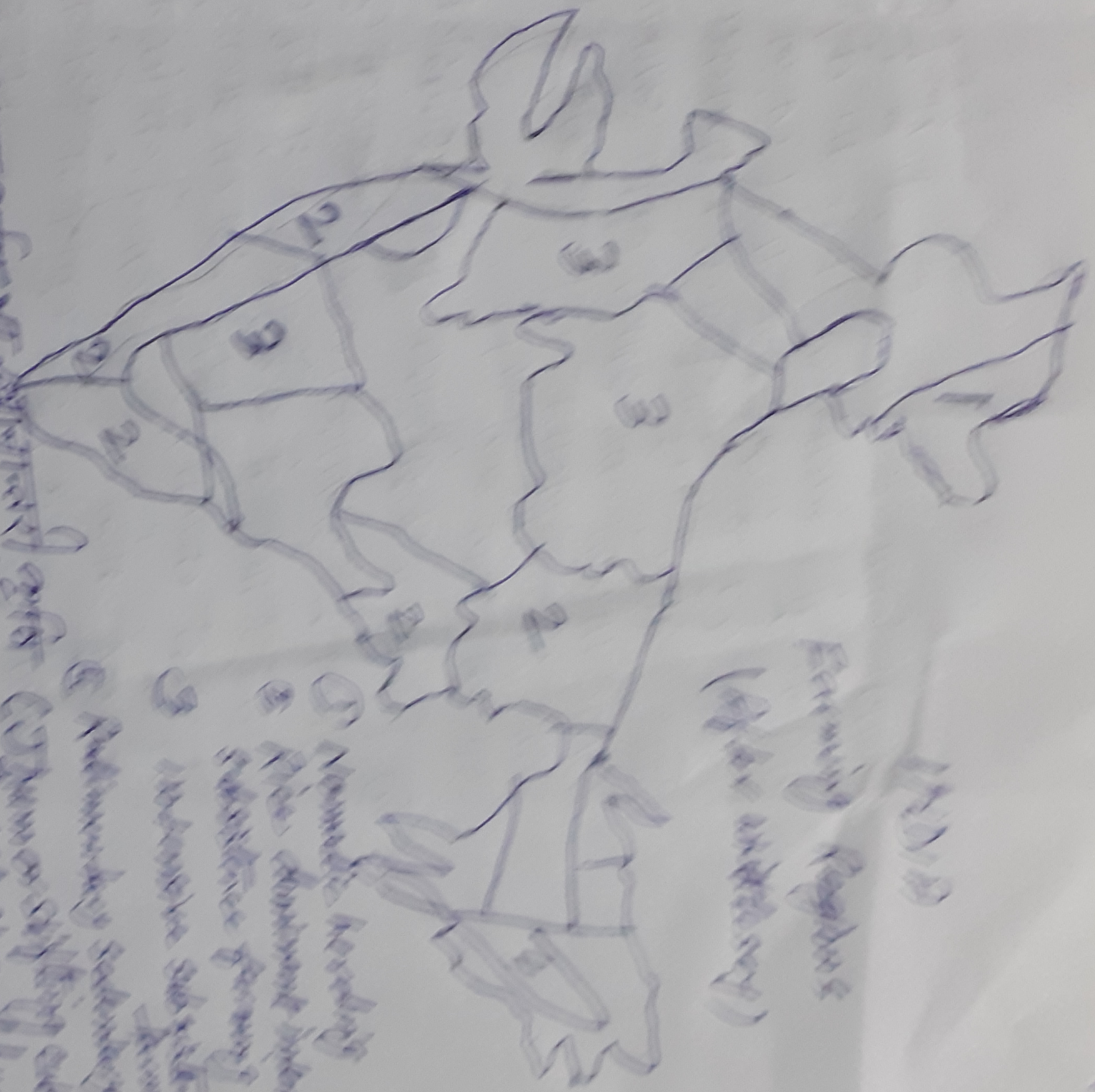

विनाश किया है तथा पहाड़ी ढालों में मिट्टी अपरदन एवं मैदानों में विनाशकारी बाढ़ों को तीव्रतर किया है। झूम कृषि देश के लगभग 43.6 लाख हेक्टेयर (1.33 प्रतिशत) पर प्रचलित है तथा एक बड़ा पर्यावरणीय संकट है। इन आदिवासियों का स्थायी कृषि अपनाने की शिक्षा देने तथा उनके पुनर्वास के लिये अनेक विशिष्ट कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

(2) निर्वाहक अन्नोत्पादक कृषि (Subsistence grain farming):
भारत में अनादिकाल से निर्वाहक कृषि प्रचलित रही है। इस प्रणाली में छोटे खेतों में पशु तथा मानव शक्ति प्रयुक्त करके, पुराने ढंग के उपकरणों की सहायता से, घरेलू माँग की पूर्ति करने के लिये खाद्य फसलें उगायी जाती हैं। इस कृषि में सिंचाई की सिंचाई की सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ से क्षति, उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों आदि का न्यून प्रयोग, मृदा अपरदन की समस्या, कम उपज की प्राप्ति, किसानों का निम्न जीवन स्तर, ऋणग्रस्तता आदि दोष पाये जाते हैं। इसमें खाद्य फसलों की प्रधानता होती है तथा वर्ष में दो या तीन फसलें सघन रूप से उगायी जाती हैं। खाद्यान्न, दालें तिलहन, सब्जियाँ आदि घरेलू माँग के लिये उगाये जाते हैं।

(3) वाणिज्यिक अन्नोत्पादक कृषि (Commercial grain
नयी कृषि रणनीति के अन्तर्गत सिंचाई, उन्नत के अधिक उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीट-नाशकों, फार्म मशीनरी आदि पर विशेष बल दिया गया है। कृषि की यह नयी पद्धति विगत तीन दशकों में देश के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में अपनायी गयी है। यह एक

पूँजी-सघन कृषि है जिसमें फसलों का अधिशेष (Surplus) उत्पादन बाजार में लाभ कमाने के लिये किया जाता है। इससे भारत खाद्यान्नों में आत्म निर्भर होने के साथ-साथ निर्यात के लिये भी उत्पादन करने लगा है।

(4) बागाती कृषि (Plantation farming):- भारत की बागाती कृषि का प्रारम्भ ब्रिटिश शासन काल में यूरोपीय बाजारों में चाय, कहवा तथा रबड़ की माँग को पूरा करने के लिये किया गया। असम, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों, कुमाँयू (उत्तराखण्ड) तथा नील गिरि की पहाड़ियों में चाय के बागान लगाये गये। कहवा तथा रबड़ के बागान कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में सीमित है। ये बागान विशाल फार्मों पर विस्तृत है तथा वाणिज्यिक स्तर पर बड़े कारखाने की भाँति इनका प्रबन्धन किया जाता है। लगभग 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बागान विस्तृत है।

भारतीय कृषि अधिकाधिक वाणिज्यिक, बाजारोन्मुख तथा विविधतापूर्ण होती जा रही है। नकदी फसलें, बागवानी, फूलों की खेती (floriculture), रेशमकीट पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि पर बल दिया जा रहा है।